



## परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास



# परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास

## 1. कोयला संरक्षण

कोयले का संरक्षण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, विशेषकर तब जब कि कोयला भण्डार सीमित हैं। कोयला संरक्षण के पहलू पर आयोजना के स्तर से ही ध्यान दिया जाता है तथा कार्यान्वयन चरण में अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। कोयला सीमों के लिए खानों का डिजाइन तकनीकी व्यवहार्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए ओपनकास्ट अथवा भूमिगत पद्धतियों के माध्यम से किया जाता है।

वर्तमान में मशीनीकृत ओपनकास्ट (ओसी) खनन उथली गहराई में थिक सीमों के निष्कर्षण के लिए आम तौर पर अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी है। यह संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से प्राप्ति का प्रतिशत लगभग 80% से 90% है। वर्तमान में, कोयला उद्योग में इस प्रौद्योगिकी की प्रबलता है और इसके माध्यम से देश के कोयला उत्पादन में 94% से ज्यादा का योगदान मिलता है। इसके अलावा, जब भी व्यवहार्य हो, भूमिगत खानों के विकसित पिलर्स का निष्कर्षण ओपनकास्ट प्रचालनों के माध्यम से किया जा रहा है।

लांगवाल पद्धति, शार्टवाल पद्धति, हाईवाल माइनिंग जैसी नवीन प्रौद्योगिकियों तथा सतत खनन प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप भूमिगत खनन (यूजी) में निष्कर्षण के प्रतिशत में वृद्धि हुई है।

रेजिन कैप्सूल वाली मशीनीकृत बोल्टिंग से रूफ सपोर्ट प्रौद्योगिकी में सुधार के परिणामस्वरूप वाइडर गैलरी स्पैन को बनाए रखना और रूफ की खराब दशाओं के अंतर्गत अधिक कारगर ढंग से सीमों का निष्कर्षण संभव हो पाया है जिसके परिणामस्वरूप कोयला संरक्षण में सुधार हुआ है।

## 2. रेत भराई

भूमिगत खानों में रेत भराई अभी भी कोयला संरक्षण का एक कारगर साधन है जिसका महत्वपूर्ण सतही संरचना, रेलवे लाइनों, नदियों, नालों आदि जैसे बिल्ट-अप क्षेत्रों के नीचे मौजूद भूमिगत कोयला सीमों से कोयला पिलर्स के निष्कर्षण हेतु व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है अन्यथा इसके परिणामस्वरूप पिलर्स में कोयला अवरुद्ध हो सकता है। रेत

भराई से विभिन्न उठानों में थिक सीमों के निष्कर्षण में भी सहायता मिलती है जिससे निष्कर्षण का प्रतिशत बढ़ा है। रेत की कमी के कारण, रेत के विकल्प के रूप में भूमिगत खानों में रेत भराई के लिए फ्लाइ ऐश, बॉइलर ऐश, क्रशड ओवरबर्डन पदार्थ आदि जैसे अन्य पदार्थों के उपयोग हेतु विभिन्न प्रायोगिक परीक्षण किए जा रहे हैं। वर्तमान में, भूमिगत कोयला खानों में रेत भराई के लिए वाणिज्यिक रूप से क्रशड ओवरबर्डन पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है, इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां खान के आस पास रेत उपलब्ध न हो या सुदूर नदी स्रोतों से रेत की दुलाई महंगी पडती हो।

## 3. परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास

### परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास

कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) के लिए कोयला नियंत्रक सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। कोयला नियंत्रक का कार्यालय प्रोसेस प्राप्त करता है और कोलफील्ड्स क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी कार्य, वैज्ञानिक विकास कार्य, सड़क और रेल अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में सीसीडीएसी के माध्यम से निधियां जारी करने हेतु कोयला कंपनियों से आवेदनों/दावों की जांच करता है।

कोयला मंत्रालय ने 13.01.2020 के का.ज्ञा. संख्या 20011/10/2019-आईएफडी के माध्यम से दो प्लान स्कीमों के लिए निम्नानुसार बजट बताया है:-

- कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा – 10.00 करोड़ रु.
- कोलफील्ड्स में परिवहन अवसंरचना का विकास – 84.48 करोड़ रु.

वर्ष 2019-20 से संरक्षण एवं सुरक्षा शीर्ष में 3.49 करोड़ रु. तथा परिवहन अवसंरचना विकास शीर्ष में 146.89 करोड़ रु. की स्पिलओवर राशि थी।

कोयला मंत्रालय ने संरक्षण एवं सुरक्षा शीर्ष में 4,068 करोड़ रु. तथा परिवहन अवसंरचना विकास शीर्ष में 11.47 करोड़ रु. की

राशि जारी की है।

#### 4. सीआईएल: रेल अवसंरचना परियोजनाएं

भविष्य में उत्पादन तथा निकासी में योजनाबद्ध वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से सीआईएल ने मुख्य रेल अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण का कार्य आरंभ किया है। इन रेल अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारतीय रेलवे (डिपॉजिट आधार पर) अथवा रेलवे, सहायक कंपनी (सीआईएल का प्रतिनिधित्व करने वाली) तथा संबंधित राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले आईआरसीओएन के साथ जेवी कंपनियों के जरिए किया जा रहा है।

तीन (03) प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाएं डिपॉजिट आधार पर और 4 रेल अवसंरचना परियोजनाएं जेवी कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

##### डिपॉजिट आधार:

ईस्ट सेंट्रल रेलवे, पटना द्वारा झारखंड में सीसीएल के नार्थ करनपुरा क्षेत्र के लिए 2399 करोड़ रु. की परियोजना लागत से लगभग 44.37 कि.मी. लम्बाई वाली तोरी-शिवपुर न्यू बीजी लाइन का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पूरी लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है तथा ओएचई सिग्नलिंग एवं कम्प्यूनिकेशन का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। वर्तमान में, इस नई बीजी लाइन के जरिए कोयला भेजा जा रहा है। 8.94 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी से तीसरी लाइन की भी योजना बनाई गई है जिससे निष्कासन क्षमता 100 एमटीवाई तक बढ़ जाएगी।

साउथ ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता द्वारा महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित आईबी वैली कोलफील्ड्स के लिए 1123.90 करोड़ रु. की लागत से लगभग 52.41 कि.मी. की लंबाई वाली झरसुगुडा-बारापल्ली-सरडेगा रेलवे अवसंरचना परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है और ये लाइन अप्रैल- 2018 में प्रारंभ हो चुकी है। 2900 करोड़ रुपए की अनुमानित पूंजी से बारपल्ली में सात लोडिंग बल्बों के साथ इस रेल मार्ग के दोहरीकरण तथा रेल फ्लाइओवर कॉम्प्लेक्स सहित झारसुगुडा यार्ड की रि-मॉडलिंग को अनुमोदन दे दिया गया है और इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

##### संयुक्त उद्यम आधार :

49.085 किमी लंबाई वाले शिवपुर-कठौतिया खंड का कार्यान्वयन सीसीएल, आईआरसीओएन तथा इसके साझेदार

के रूप में झारखंड सरकार के साथ झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) नामक जेवी कंपनी द्वारा 1799.64 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से किया जा रहा है।

ईस्ट रेल कोरिडोर का कार्यान्वयन एसईसीएल, आईआरसीओएन तथा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाई गई एक जेवी कंपनी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लि. (सीईआरएल) द्वारा दो चरणों में किया जा रहा है:

चरण-I: 3055 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से गारे-पाल्मा तक स्पर के साथ खर्सिया-धर्मजयगढ़ और लगभग 132 किमी की तीन फीडर लाइन। खर्सिया- कोरीचापर (0-45 कि.मी.) सेक्शन की शुरुआत: 12.10.2019। कोरीचापर- धर्मजयगढ़ (45-74 कि.मी.) सेक्शन में 31 दिसम्बर, 2020 तक इंजिन रोलिंग होने की आशा है। फीडर लाइनों के निर्माण के लिए सिविल निविदाएं दी जा चुकी हैं।

चरण-II: 1686.22 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से लगभग 62.5 कि.मी. लंबाई वाली धर्मजयगढ़-कोरबा। भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

एसईसीएल, आईआरसीओएन और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गठित एक जेवी कंपनी छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल), वाया दिपका, कटघोड़ा, सिंदुरगढ़ और पासन ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरिडोर (गेवरा रोड से पेंद्रा) का निर्माण कर रही है। इसकी लम्बाई 135 किलोमीटर और लगभग 35 किलोमीटर फीडर लाइनें हैं और इसकी अनुमानित लागत 4970.11 करोड़ रुपये है। रेल लाइनों के निर्माण के लिए उच्च मूल्य वाली दो सिविल निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

एमसीएल, आईआरसीओएन और ओडिशा राज्य सरकार द्वारा गठित जेवी कंपनी महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल), दो चरणों में कोयले की निकासी को पूरा करने के लिए एमसीएल के तालचेर कोलफील्ड में रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निर्माण का कार्य कर रही हैं:

**इनर कॉरिडोर:** 1700 करोड़ रुपये (भूमि की लागत को छोड़कर) की अनुमानित लागत से एमसीएल के तालचेर कोलफील्ड में अंगुल-बलराम-झारपाड़ा-टेन्टुलोई में 69.10 कि.मी. लम्बा लिंक (जिसमें 14.22 किमी लंबाई वाले झारपाड़ा-कलिंग-अंगुल की लिंक शामिल हैं)।

पहले चरण में, अंगुल-बलराम (0-13 कि.मी.) सेक्शन का निर्माण 145 करोड़ रुपए की पूंजी लागत से किया जा रहा है। इस सेक्शन में निर्माण क्रियाकलाप (0-6 कि.मी.) शुरू हो

चुका है। एमसीएल भूमि (6–13 कि.मी.) को ईसीओ रेलवे को ट्रांसफर किया जाना प्रगति पर है।

शेष हिस्से (13–69.1 कि.मी.) में भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

बाहरी कॉरिडोररू लगभग 136 कि.मी. लंबे टेंटुलोई-बुधापंक का कार्य इनर कॉरिडोर के पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा।

फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाएं

सीआईएल ने खानों में 4 एमटीवाई और इससे अधिक की 35 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं चिह्नित की हैं। 404.5 एमटीवाई वाली 35 परियोजनाओं में से 26 एमटीवाई वाली 2 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं, 8 परियोजनाएं निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं, 7 नई परियोजनाओं के लिए एलओएडब्ल्यूओ जारी किए जा चुके हैं और शेष 18 निविदा मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है। यह क्षमता वृद्धि मौजूदा 151 एमटीवाई की एफएमसी क्षमता से अधिक है। इन सभी 35 परियोजनाओं की 2023–24 तक पूरा होने की संभावना है।

## 5. एससीसीएल

**रेत भराई:**

सार्वजनिक भवन, कॉलोनियां, रेल लाइनों, सार्वजनिक सड़कें आदि जैसे महत्वपूर्ण सतही अवसंरचनाओं की सुरक्षा के लिए भूमिगत खाली स्थानोंधगोफ (कोयला निकालने के बाद) को नदी की रेत से भर (भराई) दिया जाता है। रेत की अत्यधिक कमी के कारण, एससीसीएल खानों की भूमिगत खानों में भराई के लिए रेत के विकल्प के रूप में बॉटम ऐश, बॉयलर ऐश और क्रशड ओवर बर्डन जैसे अन्य पदार्थों के इस्तेमाल के विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं।

एससीसीएल की 14 भूमिगत खानों में नदी की रेत, बॉटम ऐश और प्रोसेस्ड ओवर बर्डन द्वारा भराई की जा रही है।

अप्रैल से दिसंबर, 2020 के दौरान भूमिगत खानों में इस्तेमाल किए गए 13.11 एलसीयूएम भराई पदार्थों में से 25.5% प्रोसेस्ड ओवरबर्डन, 42% बॉटम ऐश और 32.5% नदी की रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है।

गहरी ओपनकास्ट खान के अंतिम हाई वॉल में शेष कोयले को निकालने के लिए एससीसीएल की खान में हाईवॉल खनन का

कार्य चल रहा है।

**कोयला निष्कासन के लिए रेल और अवसंरचना परियोजना:**

एससीसीएल ने 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान 32.66 मि.ट. कोयले का उत्पादन किया था और 31.79 मि.ट. का प्रेषण किया था। 2024 तक कोयला उत्पादन और प्रेषण में 80 मि.ट. तक की नियोजित बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए एससीसीएल द्वारा निष्कासन और अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं—

1. दो रेलवे परियोजनाएं अर्थात एससीसीएल के सिंगरैनी थर्मल विद्युत संयंत्र तक गोलेटी रेलवे साइडिंग और रेलवे लाइन पूरी हो चुकी हैं। सड़क के माध्यम से 5 मिलियन टन कोयले की दुलाई को समाप्त कर दिया गया है और इसकी 100 प्रतिशत दुलाई रेल द्वारा की जा रही है।
2. भद्रचलम से सत्तुपल्ली तक रेलवे लाइन की परियोजना 927.94 करोड़ रुपए (संशोधित लागत) की है जिसमें एससीसीएल का शेयर 618.55 करोड़ रुपए है। यह रेलवे द्वारा शुरू किया गया डिपॉजिट है। यह 54.1 कि. मी. लंबी रेलवे लाइन है और इसकी जून, 2021 तक पूरा होने की संभावना है। परियोजना जून, 2021 तक पूरी होने की संभावना है।
3. चल रहे रेलवे साइडिंग कार्य:
  - i. सत्तुपल्ली रेलवे साइडिंग (140.0 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 10.17 कि.मी लंबाई)।
  - ii. गोलेटी रेलवे साइडिंग (10.00 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 1 कि.मी.)।
  - कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी): 50 एमटी क्षमता के 9 सीएचपी के जरिए रेल/एमजीआर प्रणालियों द्वारा कोयला भेजा जाता है। शेष कोयले की सड़क द्वारा दुलाई की जा रही है।
  - 3 नए सीएचपी पर प्रथम माइल कनेक्टिविटी के तहत निगरानी रखी जा रही है।
  - एसआरपी सीएचपी (3.5 एमटीपीए) रु 13.01.2020 को शुरू हुआ।

- जेवीआर ओसी सीएचपी (10 एमटीपीए की क्षमता वाली): लगभग 55% कार्य पूरा हो चुका है और इसे दिनांक 30.04.2021 तक पूरा किया जाना है।
- नैनी सीएचपी (10 एमटीपीए): 2023-24 में पूरा होने की संभावना है। एमसीआरएल द्वारा रेलवे साइडिंग बनाने के बाद ही सीएचपी के डीपीआर को अनुमोदन दिया जा सकता है।

रेलवे लाइन, रेलवे साइडिंग और कोल हैंडलिंग प्लांट बनाने के अलावा निम्नलिखित व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं –

- प्रि-वे वैगन लोडिंग सिस्टम: एससीसीएल में 10 प्रि-वे वैगन लोडिंग सिस्टम और 15 ट्रक लोडिंग सिस्टम हैं जो विभिन्न खानों और कोल हैंडलिंग प्लांटों में लगाए गए हैं और काम कर रहे हैं।

- क्रशर: ओपनकास्ट खानों में स्थायी क्रशर के अलावा, 6 मोबाइल क्रशर एससीसीएल में लगाए गए हैं तथा 6 और (विभाग-5 और नियुक्ति-1) शुरुआत के विभिन्न चरणों में हैं।
- अप्रोच सड़क/ध्वीटी सड़क/एस्फाल्ट सड़करू कोयले की ढुलाई के लिए आवश्यकतानुसार सड़कें बनाई जा रही हैं और इनका रख-रखाव किया जा रहा है।

## 6. एनएलसीआईएल द्वारा किए गए प्रयास:

कोयला खानों की फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी)

तालाबीरा ii – iii ओसीपी (20 एमटीपीए):

### 1. एफएमसी उपलब्धि:

	परियोजना का नाम	शुरू करने की समय-सीमा
(प)	खनन परिचालनों की शुरुआत	2019-20
(पप)	सीएचपी, साइलो आधारित प्रेषण और मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली (एमडीओ का कार्यक्षेत्र)	अप्रैल, 2022
(पपप)	रेलवे साइडिंग	अप्रैल, 2022

### 2. खनन परिचालनों की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2020-21 (0.937 एमटीपीए):

तालाबीरा II एवं III ओसीपी में कोयला उत्पादन 26.04.2020 से आरंभ हुआ। 31.12.2020 तक संचयी कोयला उत्पादन 4.38 एल.टी. है।

### 3. सीएचपी, मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली और रैपिड लोडिंग साइडो:

सीएचपी, मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली और रैपिड लोडिंग साइलो का निर्माण एमडीओ के दायरे में आता है। डीपीआर पूरा हो चुका है, अंतिम रूप देने के लिए अनुमोदन दिया जा रहा है। वेंडर का चयन अंतिम चरण में है। स्थल को तैयार करना प्रगति पर है।

### 4. रेलवे साइडिंग (तालाबीर-II एवं III ओसीपी):

एनएलसीआईएल द्वारा 20 एमटीपीए वाली तालाबीर-II एवं III ओसीपी का विकास किया जा रहा है। खनन परिचालन 11.12.2019 से शुरू हो चुका है। कोयला उत्पादन

26.04.2020 से आरंभ हुआ था।

आरंभ में, कोयले को सड़क मार्ग से निकट के रेलवे साइडिंग तक ढुलाई की जाएगी ताकि इसकी आगे पारादीप बंदरगाह तक ढुलाई की जा सके और इससे आगे एनटीपीएल, तुतीकोरिन तक प्रेषण किया जा सके। तालाबीरा-II एवं III ओसीपी में निजी रेलवे साइडिंग बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली से कोयले की पिट हेड कोयला स्टॉक यार्ड से रेलवे साइडिंग तक ढुलाई की जाएगी। कंप्यूटरीकृत रैपिड लोडिंग सिस्टम (साइलो) के जरिए रेलवे वैगनों में कोयला लोड किया जाएगा। रेलवे साइडिंग की शुरुआत होने के बाद सड़क ढुलाई से पूरी तरह बचते हुए मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली, रेल और समुद्र जैसे विभिन्न माध्यमों के जरिए पिट हेड कोयला स्टॉक यार्ड से एनटीपीएल, तुतीकोरिन, तमिल नाडु तक कोयले की ढुलाई की जाएगी। रैपिड लोडिंग साइलो प्रणाली का निर्माण एमडीओ के दायरे में आता है।

कोयला निष्कासन के लिए व्यवहार्यता अध्ययन, प्रारंभिक इंजीनियरिंग और रेल अवसंरचना के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करने के लिए एलओए 22.10.2016 को जारी किया गया

था। मैसर्स आरआईटीईएस द्वारा अध्ययन रिपोर्ट मार्च, 2017 में प्रस्तुत की गई थी। मैसर्स आरआईटीईएस द्वारा 27.08.2018 को डीपीआर प्रस्तुत किया गया था। एसईसीआर, बिलासपुर द्वारा डीपीआर को सैद्धान्तिक अनुमोदन 21.05.2019 को दिया गया था।

#### 5. रेलवे साइडिंग की मुख्य विशेषताएं:

- एनएलसीआईएल की साइडिंग के लिए सेवारत स्टेशन रु 8 कि.मी. (लगभग) की दूरी पर आईबी स्टेशन।
- 2021-22 से प्रति दिन 6 रैक पारादीप और घाटमपुर भेजे जाएंगे।

- पूरी साइडिंग का विद्युतीकरण किया जाएगा।
- कोयला लोडिंग यार्ड में 1 इन-मोशन वे-ब्रिज प्रस्तावित है।
- कोयले की लोडिंग के लिए कोयला लोडिंग यार्ड में 01 कंप्यूटरीकृत रैपिड लोडिंग सिस्टम (साइलो) की योजना बनाई गई है।
- 1.5 घंटे में पूरा रैक लोड करने के लिए कोयला लोडिंग साइलो की योजना बनाई जाएगी।

परियोजना का नाम	पूंजी लागत (करोड़ रुपए)	शुरू करने की समय-सीमा
(सीएचपी), साइलो आधारित प्रेषण और मशीनीकृत कन्वेयर प्रणाली	एमडीओ का दायरा 369.65 (लगभग)	अप्रैल, 2022
रेलवे साइडिंग	294.87	अप्रैल, 2022

#### रेलवे साइडिंग की वर्तमान स्थिति:

- पैकेज -I के लिए मैसर्स त्रिवेणी इंजीकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड को 13.03.2020 को एलओए जारी किया गया।
- पैकेज-II के लिए मैसर्स एसएमएस लिमिटेड को 05.06.2020 को एलओए जारी किया जा चुका है।
- मैसर्स आरआईटीएस के निलंब खाते में 09.06.2020 को 18 करोड़ रुपए का मोबीलाइजेशन एडवांस का भुगतान किया गया था।
- रेलवे साइडिंग (पैकेज -II)रु 17.06.2020 से सर्वेक्षण कार्य आरंभ हुआ।

- 1.77 कि.मी. की सरकारी भूमि और वन भूमि का कार्य मैसर्स एसएमएस लिमिटेड को 10.08.2020 को सौंपा गया।
- रेल आपूर्ति के लिए तीसरे पैकेज हेतु मैसर्स सेल को 31.03.2020 को एलओए जारी किया गया।
- शेष 2 पैकेजों के लिए एलओए जारी करने का लक्ष्य जनवरी, 2021 रखा गया है।
- पूरा होने की नियत तारीख: अप्रैल, 2022

#### 6. भूमि अधिग्रहण:

- रेलवे साइडिंग के लिए भूमि की आवश्यकता निम्नानुसार है:

विवरण	काश्तकारी भूमि (एकड़)	सरकारी भूमि (एकड़)		कुल (एकड़)
		जलभंडार	अन्य	
खान पट्टा सीमा से बाहर की भूमि	23.47	30.39	8.97	62.83
खान पट्टा सीमा के भीतर की भूमि	54.22	8.02	0.00	62.24
<b>कुल</b>	<b>77.69</b>	<b>38.41</b>	<b>08.97</b>	<b>125.07</b>

क. एमएल सीमा के बाहर की भूमि:

- i. जलभंडार भूमि: विशेष सचिव, ओडिशा सरकार से अनुमोदन/अनुमति प्रतिक्षित है।
- ii. अन्य सरकारी भूमि: एनएलसीआईएल को सरकारी भूमि स्थानांतरित करने के लिए डीसी, झारसुगुड़ा को आवेदन प्रस्तुत किया गया।
- iii. काश्तकारी भूमि: झारसुगुड़ा जिले में काश्तकारी भूमि के अधिग्रहण के लिए 28.08.2020 को डीसीएसी बैठक का आयोजन किया गया और 47 खातों में से 10 खाते राउट का पंजीकरण पूरा हुआ।

ख. एमएल सीमा के भीतर भूमि:

- i. जलभंडार भूमि: विशेष सचिव, ओडिशा सरकार से अंतिम अनुमोदन/अनुमति प्रतिक्षित है।
- ii. काश्तकारी भूमि: भूमि मुआवजे का वितरण किया जा रहा है।

**पछवाड़ा साउथ ओसीपी (9 एमटीपीए):**

- i. मैसर्स एनएलसी इंडिया लिमिटेड का जेवी नेयवेली, उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) और मैसर्स उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल) दुमका जिला, झारखंड में 9 एमटीपीए का पछवाड़ा साउथ कोयला ब्लॉक विकसित कर रहे हैं।
- ii. पछवाड़ा साउथ ओसीपी से कोयला उत्पादन वर्ष 2023-24 से आरंभ होने की संभावना है।
- iii. पछवाड़ा कोलफील्ड में तीन कोयला ब्लॉक अर्थात् पछवाड़ा नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ हैं।

iv. पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) और पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) को क्रमशः निकटवर्ती पछवाड़ा नॉर्थ और पछवाड़ा सेंट्रल कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए हैं।

v. वर्तमान में, पछवाड़ा कोलफील्ड में कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है।

vi. फर्स्ट माइल रोड कनेक्टिविटी को दूर करने के लिए कोयले के निष्कासन हेतु ईआर की पाकुर-हावड़ा लाइन पर लगभग 50 किलोमीटर (दक्षिण पाकुर) की दूरी पर इस कोयला ब्लॉक को नगरनबी स्टेशन से जोड़ना प्रस्तावित है।

vii. कोयले के निष्कासन के लिए, झारखंड सरकार के सहयोग से रेल अवसंरचना के विकास हेतु मैसर्स एनयूपीपीएल और अन्य कोयला ब्लॉक आवंटितियों (मैसर्स डब्ल्यूबीपीडीसीएल और मैसर्स पीएसपीसीएल) तथा मैसर्स रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के बीच भागीदारी मॉडल आधारित एसपीवी का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

viii. मैसर्स आरआईटीईएस को परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम दिया हुआ है।

ix. लगभग 1.8 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित अलाइमेंट ऊर्मा पाहाडीतोला कोयला ब्लॉक से होकर गुजर रहा है जिसे वाणिज्यिक खनन हेतु मैसर्स ओरोंबिंदो रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किया गया था।

x. कोयलाधारक क्षेत्र से गैर-कोयलाधारक क्षेत्र तक रेलवे साइडिंग को शिफ्ट करने संबंधी सर्वेक्षण प्रक्रियारत है।

\*\*\*\*\*